

03 *जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक

06 महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी

08 पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रधान (केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पिता) का निधन

परिवहन आयुक्त के प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रेप डीलरों को विभाग ने जारी किया आदेश, आखिर क्यों?

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन आयुक्त द्वारा अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रेप डीलरों को अपने पद के बल का दुरुपयोग करने के साथ बाँक्सरो के बल पर जनता के वाहनों को उठवाने (यहां उठवाना शब्द का सही अर्थ लुटवाना) का जो कृत्य करवाया उसका बड़ा सबूत आज सामने आ ही गया। इस सबूत का अर्थ है की किसी भी परिवहन आयुक्त के प्रिय वाहन स्क्रेप डीलरों ने ना तो जनता को उनके वाहनों की स्क्रेप कीमत दी और ना ही परिवहन विभाग में जमा करवाई। इतना ही नहीं यहां यह भी जानने योग्य बाते है

1. आखिर किस की शय पर परिवहन आयुक्त के प्रिय वाहन स्क्रेप डीलरों द्वारा वाहन मालिकों या समय सीमा में पैसों को जमा क्यों नहीं करवाया ?

2. परिवहन विभाग द्वारा समय सीमा में ही कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की आखिर कौन था इसके पीछे ?

3. परिवहन आयुक्त के इन प्रिय वाहन स्क्रेप डीलरों ने जब्त किए वाहनों के पैसे तो नहीं दिए और साथ ही भारत सरकार के राजस्व

को मोटा चुना लगाया और इसकी पूर्ण जानकारी दिल्ली के परिवहन आयुक्त को है फिर भी कार्यवाही नहीं आखिर क्यों ?

इस लेखा के साथ परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश ईमेल का हिंदू रूपांतरण और कापी स्लगन

कितना जनता और सरकार का हित करने वाला है सह मुख्य सचिव एम-परिवहन आयुक्त दिल्ली

स्क्रेपसेल टीपीटी 4:29

अपराहन

अनिरुद्ध को, भरत, भारत,

जाओ, गोप्री...

ट्रेल मेल का संदर्भ लें.

सर/मैडम, सभी आरवीएसएफ

को निर्देश दिया जाता है कि वे उन

वाहनों के संबंध में पूर्ण स्क्रेप मूल्य

(राशि) सरकारी खजाने में 15

दिनों की अवधि के भीतर बिना

किसी शुल्क काटे समयबद्ध तरीके

से जमा करें, जिनके लिए स्क्रेप

मूल्य का दावा नहीं किया गया है।

खाते का विवरण इस प्रकार है:

खाते का नाम- कमिश्नर

टीपीटी- संग्रह

खाता संख्या:

0000001057752233

आईएफएससी कोड:

SBIN0005453

एमआईसीआर कोड:

110002094

इसके अलावा, यदि कोई

आरवीएसएफ स्क्रेप राशि सरकार

के पास जमा नहीं करता है।

परिवहन विभाग द्वारा जारी दिनांक

20/02/2024 को दिल्ली के

सार्वजनिक स्थानों पर जीवन

समाप्त वाले वाहनों को संभालने

के लिए दिशानिर्देश, 2024 के खंड

10 में उल्लिखित निर्धारित समय के

भीतर कोषागार में जमा कराना

होगा। जीएनसीटीडी द्वारा कारण

बताओ नोटिस जारी किया जा

सकता है, जिसके बाद संबंधित

आरवीएसएफ को ब्लैक लिस्ट

करने का आदेश दिया जा सकता

है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के पूर्व

अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हालांकि, अधिकांश

आरवीएसएफ ने सरकार को

कोई राशि जमा नहीं की है।

कोषागार से एक बार पुनः अनुरोध

है कि लावारिस वाहनों से संबंधित

धनराशि सरकारी कोषागार में जमा

कराई जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई

की जाएगी।

Government of National Capital Territory of Delhi
Transport Department: Scrapping Cell
5/9, Under Hill Road: Delhi -110054

F.24(1)/NO/SCRAP/TPT/2024/075786517/1/136 Dated 23/03/2025

ORDER

All the RVSFs are directed to deposit the full scrap value (amount) in the Govt. Treasury in respect of the vehicles for which scrap value has not been claimed within the period of 15 days in a time bound manner without deducting any charges. The details of the account are as follows:

Account Name- Commissioner TPT- Collection
Account no.: 0000001057752233
IFSC Code: SBIN0005453
MICR Code: 110002094

Further, if any RVSF does not deposit the scrap amount in the Govt. Treasury within the stipulated time as mentioned in Clause 10 of Guidelines for Handling End Of Life Vehicles in Public Places Of Delhi, 2024 dated 20/02/2024 issued by Transport Dept. GNCTD, a show cause notice may be issued followed by Blacklisting Order to the concerned RVSF.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

Deputy Commissioner
(Scrapping Cell)

Copy to:-
1. PS to ACS-cum-Commissioner, Transport Department, GNCTD.
2. PA to Special Commissioner (Scrapping/Enf), Transport Department, GNCTD.
3. All concerned RVSFs.
4. Sr. System Analyst, Transport Department, GNCTD with the request to upload on the website of Transport Department.

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in

Email : tolwadelhi@gmail.com

bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

मातृशक्ति, पूरे विश्व की प्रेरणा स्रोत थी, हैं और रहेगी

मातृशक्ति, पूरे विश्व की प्रेरणा स्रोत थी, हैं और रहेगी। इस संसार में दो सबसे बड़ी शक्तियां हे प्रकृति और नारी (मातृ शक्ति) दोनों पर हमारा अस्तित्व निर्भर है। समाज ही नहीं राष्ट्र और विश्व उत्थान के हर क्षेत्र में मातृ शक्ति का योगदान अनुकूलिणी अभूतपूर्व है,

- * स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है,
- * स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है,
- * स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है
- * मामी - मौसी- बुआ है तो स्नेह का स्तकार है,
- * स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है,
- * स्त्री अगर साथी है तो सुख की शतत संभावना है,
- * स्त्री अगर बहु-बेटी है तो परमात्मा की आत्मा है !!!
- * और अंतिम पवित्र स्त्री यदि रमाँर है तो साक्षात् रपरमात्मा है,
- * हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक मातृ शक्ति अकेली ही काफ़ी है घर, समाज और राष्ट्र को स्वर्ग बनाने के लिए।

मातृ शक्ति को सादर वंदन. सादर नमन!



संजय बाटला

विकसित दिल्ली के लिए परिवहन और यातायात प्रबंधन में बड़े बदलाव की जरूरत, जानिए एक्सपर्ट की राय

रिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-संवेदनशील शहर बनाने की दिशा में परिवहन और यातायात प्रबंधन में बड़े बदलाव की योजना पर काम की जरूरत है। दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और असम सरकार में यातायात सलाहकार अनिल छिक्रा ने विकसित दिल्ली के लिए परिवहन और यातायात प्रबंधन में क्या बदलाव होने चाहिए इसका एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत बस सेवाओं से लेकर निजी परिवहन, ई-रिक्शा, टैफ़िक नियंत्रण और सड़क सुरक्षा तक व्यापक सुधार किए जाएंगे। योजना का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक व कुशल



बनाना है, जिससे टैफ़िक जाम और प्रदूषण को कम किया जा सके। क्योंकि आज की स्थिति ये है कि टैफ़िक जाम से हर राहगीर परेशान है। डीटीसी बस सेवा में बदलाव

की जरूरत: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) को नई तकनीक और प्रभावी रूटिंग के साथ अपग्रेड किया जाए, इसके तहत बसों के नए मॉडल लाने, जोन-आधारित

रूटिंग और डिजिटल किराया प्रणाली लागू करने की योजना लागू हो। लंबी दूरी की बसों को कम किया जाएगा, जिससे शहर में भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके।

अब दिल्ली होगी जाम मुक्त....

दिल्ली में टैफ़िक जाम की समस्या से निपटने के लिए टैफ़िक पुलिस कमर कस रही है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर टैफ़िक पुलिस परिवहन विभाग एनडीएमसी एमसीडी और रोड इंजीनियरिंग से जुड़े विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। टैफ़िक विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सड़कों की हालत में सुधार नहीं होता तब तक जाम की समस्या से निपटा नहीं जा सकता।

नई दिल्ली। दिल्ली में वर्षों से टैफ़िक जाम एक बड़ी समस्या रही है। सुबह और शाम के पीक आवर्स में आमतौर पर लगभग सभी जगहों पर जाम लगता है। इसके अलावा अन्य समय में भी अलग-अलग कारणों से कहीं भी जाम लग जाता है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

समाधान निकालने की कोशिशें तेज दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राजधानी की इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर टैफ़िक पुलिस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए परिवहन विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी, रोड इंजीनियरिंग से जुड़े विभागों के साथ विचार-विमर्श में जुटी है। हर तरह की कवायद चल रही है।

मैनपावर बढ़ाने पर भी विचार टैफ़िक विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सड़कों की हालत में सुधार नहीं होता, तब तक जाम की समस्या से निपटा नहीं जा सकता। दूसरी ओर टैफ़िक में मैनपावर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

टैफ़िक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बेहतर टैफ़िक प्रबंधन के लिए कम से कम आठ हजार कर्मियों की जरूरत

है। टैफ़िक पुलिस में फिलहाल 4791 कर्मी तैनात हैं। इसका मतलब है कि प्रणाली में सुधार के लिए 3,000 से अधिक कर्मियों की आवश्यकता होगी।

8 हजार जवानों की तैनाती की जरूरत मुख्यालय सूत्रों के अनुसार मैनपावर को लेकर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की ओर से ऑडिट कराया जा रहा है। यह भारत सरकार की एक संस्था है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को लिखे पत्र में टैफ़िक यूनिट में 8 हजार जवानों की तैनाती की जरूरत बताई गई है।

जानकारी के अनुसार 2021 में टैफ़िक पुलिस की जो क्षमता है, उससे फिलहाल एक हजार कम है। यानी इस यूनिट के एक हजार जवान हटा दिए गए, जबकि राजधानी में टैफ़िक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी इस मुद्दे को लेकर पुलिस मुख्यालय में टैफ़िक पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के बीच बैठक हुई।

यह काउंसिल सड़कों के हिसाब से ऑडिट कर रही है कि राजधानी में टैफ़िक यूनिट में कितने जवानों की जरूरत है। भविष्य को लेकर भी आकलन किया जा रहा है। यह काउंसिल दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि पुलिस की दक्षता बढ़ाई जा सके, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके, सुरक्षा और विश्वसनीयता कायम रखी जा सके और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

डीटीसी बसों का खराब होना भी समस्या पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में डीटीसी बसों का खराब होना भी एक बड़ी समस्या है। हर राज्य की करीब 350 बसें राजधानी की सड़कों पर खराब हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य वाहन भी खराब हो जाते हैं। ऐसे मामलों से जल्दी निपटने के लिए परिवहन विभाग से मदद ली जा रही है।

पुरानी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला अगले कुछ महीनों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी

दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने वाली है। दिल्ली सरकार ने पुरानी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया है। अगले कुछ महीनों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। इससे प्रदूषण कम करने और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने में मदद मिलेगी। वहीं पुरानी बसों का इस्तेमाल रेस्तरां के तौर पर करने की योजना है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की राजधानी की सड़कों पर आगामी कुछ दिनों में अधिकाधिक इलेक्ट्रिक बसें चलती दिखाई देंगी। दिल्ली सरकार पुरानी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार अगले कुछ महीनों में पुरानी सीएनजी बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना बना रही है। अधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर उन्हें मार्च के अंत तक



● सीएनजी बसों के बेड़े में से 50 प्रतिशत को हटा दिया गया

उन्होंने कहा कि विभाग मार्च के अंत तक 1,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने पर काम कर रहा है। बता दें कि डीटीसी के सीएनजी बसों के बेड़े में से 50 प्रतिशत को हटा दिया गया है और शेष बसें अगले कुछ महीनों में सेवा से बाहर हो जाएंगी।

● खटारा बसों का इस्तेमाल रेस्तरां के तौर पर होगा

डीटीसी की खटारा बसों को अब किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। डीडीए इन बसों को यमुना किनारे खड़ा करेगा। किचन भी बस के अंदर ही होगा व बैटकर खाने की व्यवस्था भी। इस महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने काम भी शुरू कर दिया है। अभी जिस बस को रेस्तरां में बदलने का प्लान बनाया जा रहा है, वह टाटा मार्कोपोलो मॉडल एसी सीएनजी लो फ्लोर बस है। यह 2010 का मॉडल है। बस में 36 यात्री सीटें, इंजन तथा सभी इंटीरियर लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग भी है। बस की उम्र पूरी हो चुकी है।

1,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में तेजी लाने को कहा। विभाग के एक वरिष्ठ

अधिकारी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में

2,400 सीएनजी बसें और 1,700 इलेक्ट्रिक बसें हैं। परिवहन मंत्री ने पुरानी

बसों के संबंध में एक बैठक की जिनकी आयु लगभग समाप्त होने वाली है।

भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, मिथुन राशि के जातक



ज्योतिषाचार्य पं योगेश पौराणिक

गुण और स्वभाव: मिथुन राशि के लोग मध्यम कद काटी के, मोटी गर्दन वाले, घुंघराले बाल लिए, मनमोहक छवि के होते हैं। इनकी शौड़ी में गड्ढा होता है और हाथ पतले होते हैं। मिथुन राशि के लोग पढ़ने लिखने के शौकीन, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। इन्हें इंडोर खेल में काफी रुचि होती है। यह काफी टार्किंग और बातूनी तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। मिथुन राशि के लोग काफी कामुक और प्रेम सक्रिय होते हैं। जीवन साथी से जल्दी गुस्सा होना फिर जल्दी मान जाना इनका स्वाभाविक गुण होता है। कभी कभी यह चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा जिंदादिल होने की वजह से धोखे के शिकार हो जाते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के साथ घूमना, दोस्ती करना इन्हें काफी भाता है। मिथुन राशि के लोग काफी संवेदनशील और परिवर्तनशील होते हैं। यह किसी भी कार्य की योजना बनाने में काफी कुशल होते हैं।
कैरियर: मिथुन राशि के लोग कुशल गणितज्ञ, मैनेजर, लेखक, कवि,



बैंकिंग अधिकारी, आयात निर्यात, टेलीफोन संचालक, चिकित्सक, समीक्षक, अंतरिक्ष अनुसंधान, जुआ, लॉटरी, शेयर आदि के दलाल, कॉम्प्यूटर, गायक, एयर फोर्स, क्लर्क, सूती वस्त्र उद्योग, टीचिंग आदि में अपना कैरियर बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
रोग: मिथुन राशि के लोगों को थायरॉयड, टी बी, सर्दी खांसी, अतिसार, हड्डी टूटना, निर्मानिया या छाती

से सम्बन्धित रोग आदि हो सकते हैं।
भाग्यशाली दिन: सोम, बुध, गुरु और शुक्र
भाग्यशाली रंग: हरा, पीला और सफेद
भाग्यशाली अंक: 3, 5, 6, 7
शुभ रत्न: पन्ना
उपाय: मिथुन राशि के जातक को पूर्णिमा का व्रत तथा भगवान विष्णु और गणेश जी की उपासना करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं।

हमारे जीवनभर का निचोड़ ही अगले जन्म का बीज बनता है

मरते क्षण की अंतिम चाह दूसरे जीवन की प्रथम घटना बन जाती है जो इस जीवन में अंतिम है, यह दूसरे जीवन में प्रथम बन जाता है। जैसे रात को जब हम सोते हैं तो जो रात सोते समय हमारा आखिरी विचार/भाव होता है वही सुबह जागते समय हमारा पहला विचार/भाव बन जाता है। इसे तो हम अपने अभ्यास से सुनिश्चित कर ही सकते हैं और इसी तरह मृत्यु महानिद्रा है, बिल्कुल बड़ी नींद की तरह है। बस फर्क इतना पड़ता है के तब हम इस शरीर में नहीं

जागते दूसरे शरीर में जागते हैं। लेकिन इस जीवन का जो अंतिम विचार/वासना/कामना/पकड़ होती है, वही दूसरे जीवन का प्रथम विचार, प्रथम वासना बन जाती है। इसीलिये अंतिम समय में प्रभु स्मरण लाभकारी होता है। तदनुसार प्रतीकाल्प/सिम्बोलिक रूप से, सभी अपने बच्चों के नाम प्रभु का समानार्थी रखा करते थे। लेकिन अब तो वह भी संकल्पना विलीन होती जा रही है और बच्चों के नाम भी संजु/मंजु/सोनु/मोनु/सन्नी/विकी, रखकर अपने आप

को हम पढ़ा-लिखा सभ्य मानने लगें हैं। साथ ही ध्यान रहे कि यदि जीवनभर हमने निंदा/कुकृत्य का अभ्यास किया है तो इसी अभ्यास की ही प्रधानता मृत्यु के क्षण भी बनी रहेगी। यदि जीवनभर हमने प्रभु स्मरण/प्रभु धन्यवाद/जीवन अध्ययन किया है तो यही अभ्यास हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में हमारी रग-रग में होगा। जीवन भर का अभ्यास, जीवन का आखिरी फल बनता है और वही अगले नये जीवन के पहले बीज के रूप में निरूपित होना बिल्कुल सहज/स्वाभाविक है।

शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ पाने के लिये उपाय:-

- यम-नियमों का अभ्यास इसका सबसे बड़ा साधन है। यम व नियम संक्षेप से नीचे दिये जाते हैं।
- यम (सामाजिक)
 - १. अहिंसा (किसी सज्जन और बेगुनाह को मन, वचन या कर्म से दुःख न देना)
 - २. सत्य (जो मन में सोचा हो वही वाणी से बोलना और वही अपने कर्म में करना)
 - ३. अस्तेय (किसी की कोई चीज बिना पूछे न लेना)
 - ४. ब्रह्मचर्य (अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना विशेषकर अपनी नीच इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण)
 - ५. अपरिग्रह (सांसारिक वस्तु भोग व धन आदि में लिपन होना)
- नियम (व्यक्तिगत)
 - १. शौच (मन, वाणी व शरीर की शुद्धता)
 - २. संतोष (पूरे प्रयास करते हुए सदा प्रसन्न रहना, विपरीत परिस्थितियों से दुःखी न होना)
 - ३. तप (सुषु, दुःख, हानि, लाभ, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, डर आदि की वजह से कभी भी धर्मको न छोड़ना)
 - ४. स्वाध्याय (अच्छे ज्ञान, विज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रयास करना)
 - ५. ईश्वर प्रणिधान (अपने सब कामों पर ईश्वर का नाम लेना जैसे कि ईश्वर सदा देख रहा है और फिर काम करके उसके फल की चिंता ईश्वर पर ही छोड़ देना)

सफलता अंतिम नहीं है और असफलता घातक नहीं है।

आजो बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता है। मैजिक हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, और हम सभी में है। यह हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी ऊर्जा और हमारे इरादों से बनता है। भरोसा और उम्मीद ही वह शक्ति है जिससे हम अहम्य को भी देख सकते हैं, अविश्वसनीय पर विश्वास कर सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अपने उन पुराने दिनों को कभी नहीं भूलना है जब हम उन चीजों के लिए प्रार्थना करते थे जो आज हमारी हैं। सफल होने बाद आदमी पहला काम करता है, मोटिवेशन, स्वयं एक अच्छा मोटिवेटर बन जाता है। लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं लाभ भी मिलता है सुनने वाले को भी शाश्वत। यूट्यूब पर अच्छे मोटिवेटर हैं लेकिन जब उनके विरुद्ध अफवाह फैली या डाउनफॉल आया तो वो स्वयं कमबैक नहीं कर पाए। जानो मानो और समझो स्वयं से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है।

हम बदलें तो दुनिया बदले

बूढ़ा अमरनाथ की कथा

पाकिस्तानी क्षेत्र से तीन ओर से घिरी सीमावर्ती पुंछ घाटी के उत्तरी भाग में पुंछ कस्बे से 23 किमी की दूरी पर स्थित का मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की कथा भी सुनाता है जो इस क्षेत्र में है। वैसे यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कथा सुनाई थी उसकी शुरुआत बुढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी और अब यह मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शनों के बिना अमरनाथ की कथा ही नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा भी अधूरी है। कितने आश्चर्य की बात है कि हिन्दुओं का धार्मिक स्थल होने के बावजूद इसके आसपास कोई हिन्दू घर नहीं है और इस मंदिर की देखभाल आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवार तथा सीमा सुरक्षा बल के जवान ही करते हैं। बुढ़ा अमरनाथ मंदिरों की नगरी जम्मू से 246 किमी दूरी पर स्थित पुंछ घाटी के राजपुरा मंडी क्षेत्र, जहाँ तक पहुँचने के लिए किसी प्रकार की पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती है और जिसके साथ ही कश्मीर का क्षेत्र तथा बहुत ही खूबसूरत लोचन घाटी लगती है, में स्थित बुढ़ा अमरनाथ का मंदिर चकमक पत्थर से बना हुआ है। यह सभी अन्य शिव मंदिरों से पूरी तरह से भिन्न है। मंदिर की

चारदीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी की गई है जो सदियों पुरानी बताई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा सुनाई जाने वाली अमरता की कथा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के कदमों में ही स्थित मंदिर के आसपास के पहाड़ सालभर बर्फ की सफेद चादर से ढँके रहते हैं जो हमेशा ही एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करते हैं। मंदिर के एक ओर लोचन दरिया भी बहता है जिसे 'पुलस्त्य दरिया' भी कहा जाता है और उसका पानी बर्फ से भी अधिक ठंडक लिए रहता है। सनद रहे कि पुंछ कस्बे का पहला नाम पुलस्त्य ही था। बर्फ से ढँके पहाड़, किनारे पर बहता शुद्ध जल का दरिया तथा चारों ओर से घिरे ऊँचे पर्वतों के कारण यह रमणीक स्थल हिल स्टेशन से कम नहीं माना जाता है। राजपुरा मंडी तक जाने के लिए चंडक से रास्ता जाता है जो जम्मू से 235 किमी की दूरी पर है तथा जम्मू-पुंछ राजमार्ग पर पुंछ कस्बे से 11 किमी पहले ही चंडक आता है। बुढ़ा अमरनाथ के दर्शनार्थ आने वाले किसी धर्म, मजहब, जाति या रंग का भेदभाव नहीं करते हैं। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित इस मंदिर की रखवाली मुस्लिम ही करते हैं। सिर्फ राजौरी-पुंछ से ही नहीं, बल्कि



देशभर से लोग चकमक पत्थर के लिंग के रूप में विद्यमान भगवान शिव के दर्शनार्थ इस मंदिर में आते हैं। विभाजन से पहले यहाँ पाकिस्तानी तथा पाक अधिकृत कश्मीर से आने वालों का ताँता भी लगा रहता था जो पुंछ कस्बे से मात्र तीन किमी की दूरी पर ही है। जिस प्रकार कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन, जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है, प्रत्येक वर्ष

मेला लगता है ठीक उसी प्रकार इस पवित्र स्थल पर भी उसी दिन उसी प्रकार का एक महान मेला लगता है और अमरनाथ यात्रा की ही भाँति यहाँ भी यात्रा की शुरुआत होती है और उसी प्रकार 'छड़ी मुबारक' रवाना की जाती है। त्रयोदशी के दिन पुंछ कस्बे के दर्शनार्थ आने वाले धर्मस्थल के लिए छड़ी मुबारक की यात्रा आरंभ होती है। पुलिस की टुकड़ियाँ इस चाँदी की पवित्र

छड़ी को, उसकी पूजा के उपरांत, इसका आदर सम्मान करती हैं और फिर अखाड़े के महान् द्वारा पुंछ से मंडी की ओर जुलूस के रूप में ले जाई जाती है। इस यात्रा में हजारों साधु तथा श्रद्धालु भी शामिल होते हैं जो भगवान शिव के लिंग के दर्शन करने की इच्छा लिए होते हैं। हालाँकि हजारों लोग पूर्णिमा से पहले ही सालभर लिंग के दर्शन करते रहते हैं।

शिव पूजा की उपासना पद्धतियाँ

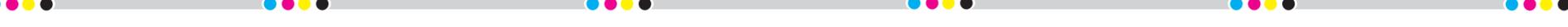
- शिव पूजा प्रयासनांतर्गत पिंडी की पूजा
- (१) शिवपिंडी की परिक्रमा कैसे करे ?
- (२) शिवपिंडी की परिक्रमा करने समय ब्रह्मा के स्त्रोत को क्यों नहीं ताँते ?
- (३) शिवपिंडी की परिक्रमा करने का उपाय
- (४) शिवपिंडी पर लक्ष्मी-कुम्भक वधाने की प्रेरणा
- (५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (११) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (२९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (३९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (४९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (५९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (६९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (७९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (८९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९०) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९१) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९२) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९३) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९४) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९५) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९६) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९७) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९८) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (९९) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय
- (१००) शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपाय

विपरीत परिणाम होता है। इससे देवता एवं धनंवर्य इव वायु के प्रहार में अकण्टक निगमन से जाती है तथा उस ओर से शिव की तम प्रणय तब करी सगुण तर्जें पृथ्वी तथा तेज तत्वों के प्राबल्य के साथ प्रदीप्त होती रहती है। परिणामस्वरूप व्योता को अग्रवक्र भ्रिजो आना, भ्रुं से केन अग्रत प्रोत्रा आना, देह में अग्रता निर्माण लेकर देह का तत्व लेना, रक्षिणं टेडी लेना, दांत अनाह भ्रैस कण्ट लेने की आशंका रहती है, इतिरि एसे शिवलिंग की अर्थ गौताकृति पद्धति से परिक्रमा करते हैं। शिवपिंडी की परिक्रमा पूरी करने के उपरांत कुछ शिवकर्म शिव अग्रसना में शिव मूर्ति स्नान, शिव कवच इनका पाठ विशेष रूप से करते हैं। पाठ करने के साथ ही शिवकवच का अधिकाधिक ताम्रय के लिए शशाशिवकर्म पर शिवपिंडी के नाम का श्राद्ध करिक्रमा करने।

15. पिंडी की स्नान कथा
शिवपिंडी की पिंडी को उठें जात, दूध एवं पंचामृत से स्नान करते हैं। योद्धवीं श्राद्धि से पूर्व शिवपिंडी को पिंडी को केवल जल से स्नान करवाना जाता था, दूध एवं पंचामृत से नहीं। दूध एवं ही 'श्रीमति' के प्रतीक है, इतिरि 'लघु' के प्रतीक शिवपिंडी की पूजा में उनका उपयोग नहीं किया जाता था। योद्धवीं श्राद्धि में दूध को शक्ति का प्रतीक मानकर प्रदाति पंचामृत, स्नान, दुग्ध स्नान इत्यादि प्रणाम आ। किसी भी देवता पूजा में मूर्ति को स्नान करने के उपरांत शिवपिंडी की परिक्रमा करवाना जाता है। परंतु शिवपिंडी की पिंडी को पूजा में लक्ष्मी एवं कुम्भक निधिर्भ्र माना गया है।

करने के उपरांत उससे बिल्वपत्र तोड़ना आरंभ करना चाहिए। शिव पिंडी की पूजा के समय बिल्वपत्र को श्रेष्ठ रख एवं उसके उलट को अग्रणी और कर पिंडी पर बढाते हैं। शिव पिंडी पर बिल्वपत्र को श्रेष्ठ बढाने से उससे निर्गुण स्तर के स्यंदन श्रेष्ठ प्रदीप्त होती है। इसीलिए बिल्वपत्र से श्रद्धालु को श्रेष्ठ लाभ मिलता है। सोमवार का दिन, वृत्तीय, अशुकी, नवमी, चतुर्दशी तथा अनावस्था, ये तिथियाँ एवं संक्रांतिका काल बिल्वपत्र तोड़ने के लिए निषिद्ध माना गया है। बिल्वपत्र शिवपिंडी को बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्वपत्र श्रेष्ठ बढा सकते हैं। बिल्वपत्र में देवता तद्व श्रद्धालुका भाग में दिखमान होता है। तब कई दिनों तक बना रहता है।

१. ब्रह्म मंडल में विद्यमान शिवस्वरूप वैद्यक्य की निर्गुण-सगुण तर्जें बिल्वपत्र से आकृष्ट होती है। २. बिल्वपत्र में शक्ति विद्यमान होती है। ३. बिल्वपत्र से धूसर रंग के निर्गुण शिवतत्व के वलयों का प्रक्षेपण होता है। ४. वातावरण में वैद्यक्य के वलयों का भी प्रक्षेपण होता है। ५. वातावरण में शक्ति के कणों का प्रक्षेपण होता है। ६. कालानुसार आवश्यक उपासना आक्रतक विधिप्र प्रकार से देवताओं का अनादर किया जाता है, इसके कुछ उदाहरण तर्जें बिल्वपत्र से आकृष्ट होती हैं देवी-देवताओं की अग्रवक्राणा करना, कला स्वयंभवा के नाम पर देवताओं के नवम धिय बनाना, व्याख्यान, पुस्तक आदि के नाशय से देवताओं पर टीका-टिप्पणी करना, व्यावसायिक डिवायि के लिए देवताओं का 'मौलद' के रूप में उपयोग किया जाना, उपादन्यों पर देवताओं के चित्र प्रकाशित करना तथा देवताओं की देशभूषा पसवकर श्रेष्ठ गौतना इत्यादि अनेक प्रकार दिखाई देते हैं। वही सब प्रकार शिवपिंडी के दर्शन में भी होते हैं। देवताओं की उपासना का मूल हे श्रद्धा। देवताओं के इस प्रकार के अनादर से श्रद्धा पर प्रभाव पड़ता है, तथा धर्म की लिंग होती है। धर्म लिंग कालानुसार आवश्यक धर्मगतत्व है। यह देवता की सम्बन्धित अर्थात् समाज के स्तर की उपयत्ना है। इसके बिना देवता की उपासना परिपूर्ण से ही नहीं सकती। इतिरि इन अग्रवक्रों को श्रेष्ठयन द्वारा बर्ही सकती प्रयास करें। जो अर्वाक के अग्रवक्रों, अर्थात् सवद, राज तथा कल को एक साथ बढ कर श्रेष्ठ निर्गुणतायै करते हैं।



दिल्ली में विकास की नई शुरुआत – मंत्री प्रवेश वर्मा की ऐतिहासिक पहल, 100 दिनों में दिखेगा बदलाव

मुख्य संवाददाता/ सुष्मा राणी

नई दिल्ली – दिल्ली में वर्षों से लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐतिहासिक पहल की है। अब हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रख रहे हैं, और संबंधित विभागों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए जा रहे हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "पहले कार्य इसलिए नहीं हुए क्योंकि नीयत नहीं थी, लेकिन अब भाजपा सरकार युद्धस्तर पर काम करके दिल्लीवासियों को राहत देगी।"

PWD मंत्री वर्मा ने जोर देकर कहा कि इस पहल का असर अगले 100 दिनों में जमीनी स्तर पर नजर आएगा। इस बैठक में PWD, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल हुए। खास बात यह रही कि इसमें संबंधित क्षेत्रों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।



बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:

- ✓ सड़कों और नालों की मरम्मत
- ✓ सीवर सफाई और जल निकासी प्रबंधन
- ✓ जलभराव की समस्या का समाधान

✓ अवैध कब्जों पर कार्रवाई

- ✓ लंबित विकास परियोजनाओं में तेजी

मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान:

"दिल्ली में वर्षों से कोई काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार की

नीयत साफ नहीं थी। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है। हम सड़कों की मरम्मत, सीवर की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। हमारी

प्राथमिकता विकास है और अगले 100 दिनों में जनता को जमीन पर बदलाव नजर आएगा। हम अधिक से अधिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। भाजपा सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि लोगों की सेवा के लिए काम करती है।"

इन विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा हुई:

बैठक में त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर (पूर्वी क्षेत्र), मुंडका, नांगलोई जाट, मोती नगर, माधिपुर (पश्चिमी क्षेत्र), मंगलापुरी, शकरपुर, किराड़ी (उत्तर-पश्चिम क्षेत्र) सहित अन्य विधानसभाओं की समस्याओं पर चर्चा हुई।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने दोहराया कि भाजपा सरकार सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। यह पहल दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनता को त्वरित राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दक्षिणी दिल्ली में सीवर की सफाई करते समय तीन फंसे, एक की मौत और दो अस्पताल में भर्ती



दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर की सफाई के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि रविवार शाम करीब 5.45 बजे दिल्ली जल बोर्ड के बोर्ड के सीवर की सफाई करते समय पंथ लाल चंद्रा की मौत हो गई। घायलों, रामकिशन चंद्रा और शिव दास, जिनकी उम्र 35 और 25 वर्ष है, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमों ने तीनों को बेहोशी की हालत में मैनहोल से बाहर निकाला। अस्पताल में पंथ लाल चंद्रा की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि बीएनएस की धारा 105 और मैनुअल स्कैविजिंग एक्ट की धारा 7 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना पर डीजेवी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

पंथ लाल चंद्रा की मौत

पुलिस ने एक बयान में कहा कि रविवार शाम करीब 5.45 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सीवर की सफाई करते समय पंथ लाल चंद्रा की मौत हो गई। घायलों, रामकिशन चंद्रा और शिव दास, जिनकी उम्र 35 और 25 वर्ष है, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीमों ने तीनों को बेहोशी की हालत में मैनहोल से बाहर निकाला। अस्पताल में पंथ लाल चंद्रा की मौत हो गई।

पुलिस ने कहा कि बीएनएस की धारा 105 और मैनुअल स्कैविजिंग एक्ट की धारा 7 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना पर डीजेवी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक



मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। जंतर मंतर: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आज आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असाद मदन ने वक्फ एक्ट में किए जा रहे संशोधन को देश के संविधान और उसके बुनियादी ढांचे पर एक गंभीर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह उस रूपरेखा को विकृत करने का प्रयास है, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत के लिए तैयार किया था। आज हमारे घरों, मस्जिदों और मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब संविधान पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है।

मौलाना मदन ने कहा कि कुछ लोग इसे केवल मुसलमानों का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह पूरे देश का मुद्दा है। हमें इस साजिश का हर हाल में विरोध करना है, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो संविधान

और लोकतंत्र में विश्वास रखता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह देश बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों का है, और हमें सिर्फ अपने साथ ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को जोड़ना होगा जो इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में विश्वास रखता है। अगर हम सभी मिलकर, सभी चिंतित नागरिकों को साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तो सफलता निश्चित होगी।

मौलाना मदन ने इस मौके पर कहा कि हर बड़ी लड़ाई कुर्बानों की मांगती है। अगर हम यह उम्मीद करें कि यह लड़ाई आराम से बैठे-बैठे जीत ली जाएगी, तो यह हमारी भूल होगी। हमें कुर्बानों देने के लिए तैयार रहना होगा, अपनी आवाज को और मजबूत बनाना होगा और अपनी कतारों में एकता पैदा करनी होगी।

अंत में, उन्होंने एक शेर कहकर अपनी बात पूरी की: थोड़ी तकलीफ-ए-रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफ-ए-दार उसके बाद ऐ दोस्तों, आराम ही आराम है

'इंडिया' शब्द को बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने पर जल्द करें फैसला', दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए केंद्र को निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 'इंडिया' शब्द को भारत या हिंदुस्तान से बदलने पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता नमहा ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर शीघ्र अदालत ने 2020 में इसे प्रतिवेदन के रूप में संबंधित मंत्रालयों को विचार के लिए भेजा था। अब कोर्ट ने मंत्रालय को जल्द निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली। केंद्र से संविधान में संशोधन करने और 'इंडिया' शब्द को भारत या हिंदुस्तान से बदलने के लिए एक प्रतिवेदन पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शीघ्रता से पालन करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। इसमें कहा गया कि केंद्र के वकील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के शीघ्र अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालयों को उचित रूप से अवगत कराना चाहिए।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने उक्त निर्देश के साथ याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता नमहा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और इस पर शीघ्र अदालत ने वर्ष 2020 में निर्देश दिया था कि याचिका को एक प्रतिवेदन के रूप में लेकर उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा सकता है। मंत्रालय को जल्द से जल्द निर्णय लेने के निर्देश



इसके बाद याचिकाकर्ता नमहा ने विरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सागर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर याचिकाकर्ता को उनके आवेदन पर निर्णय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने मंत्रालय को जल्द से जल्द निर्णय लेकर याचिका को सूचित करने का निर्देश दिया।

SC के फैसले पर केंद्र की तरफ से कोई अपडेट नहीं: याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता ने शुरू में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 2020 में

निर्देश दिया था कि याचिका को एक अर्थावेदन के रूप में माना जाए जिस पर उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा सकता है। याचिका में कहा गया, रयाचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि याचिकाकर्ता के आवेदन पर लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में केंद्र की ओर से कोई अपडेट नहीं है।

'इंडिया' देश की संस्कृति-परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता:

याचिका में कहा गया है कि अंग्रेजी नाम 'इंडिया' देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसका नाम बदलकर 'भारत' करने से नागरिकों को औपनिवेशिक बोझ से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। इसलिए याचिका में संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की गई है, जो संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है।

1948 में भी भारत या हिंदुस्तान करने की मांग की थी:

याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन मौलाना संविधान के अनुच्छेद 1 पर 1948 की संविधान सभा की बहस का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि उस समय भी देश का नाम 'भारत' या 'हिंदुस्तान' रखने के पक्ष में मजबूत लहर थी। हालांकि, अब समय आ गया है कि देश को उसके मूल और प्रामाणिक नाम यानी भारत से पहचाना जाए, खासकर तब जब हमारे शहरों का नाम बदलकर भारतीय लोकाचार के साथ पहचान की जा रही है।

क्या महिला किसानों तक पहुँच रही है तकनीक ?

भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियाँ, जिनमें कृषि, पशुधन, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं, महिलाओं के भुगतान और अवैतनिक श्रम दोनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। महिलाएँ भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं, खाद्य उत्पादन, पशुधन प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूर्णकालिक ग्रामीण कार्यबल का लगभग 75% हिस्सा महिलाओं का है और वे कृषकों का 33% हिस्सा हैं। उनकी भागीदारी बुवाई, निराई, कटाई, कटाई के बाद प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग और पशुधन देखभाल जैसी विभिन्न गतिविधियों में फैली हुई है। उनके आवश्यक योगदान के बावजूद, भूमि स्वामित्व एक चुनौती बनी हुई है, जिसमें केवल 12-13% महिला किसानों के पास भूमि का स्वामित्व है। हालाँकि, डिजिटल तकनीकों और छोटी पहलों में प्रगति कृषि में लैंगिक अंतर को कम करने में मदद कर रही है, महिलाओं को अधिक स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्थिर और निर्णय लेने में प्रभावशाली बनने के लिए सशक्त बना रही है। इन उपक्रमों को और बढ़ाने के लिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, स्मार्टफोन तक पहुँच में सुधार करना और नीति समर्थन प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा।

प्रियंका सौरभ

डिजिटल तकनीक और छोटे-मोटे हस्तक्षेपों ने भारतीय कृषि में महिलाओं के लिए परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है। इन नवाचारों ने महिला किसानों को भूमि स्वामित्व, बाजार तक पहुँच, वित्तीय समावेशन और ज्ञान के आदान-प्रदान से सम्बंधित पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने में सक्षम बनाया है। डिजिटल उपकरण कृषि में महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। एप्लिकेशन और हेल्पलाइन वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, इष्टतम कृषि तकनीक और वर्तमान बाजार मूल्य

प्रदान करते हैं। किसान सुविधा, पूसा कृषि और इफको किसान ऐप जैसे संसाधन महिला किसानों को अच्छी तरह से सूचित विकल्प बनाने में सहायता करते हैं। क्लॉसएप ग्रुप और यूट्यूब ट्यूटोरियल सहकर्मी सीखने और ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग सहित डिजिटल भुगतान प्रणाली महिलाओं को सीधे ऋण और सब्सिडी सुरक्षित करने में सक्षम बनाती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड और डिजिटल माइक्रोफाइनेंस प्लेटफॉर्म, जैसे कि पेटीएम और नाबार्ड के ई-शक्ति, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) और एपीबीएन जैसे प्लेटफॉर्म महिला किसानों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की अनुमति देते हैं, जिससे बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती।

महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियाँ अपने जैविक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग कर रही हैं। एआई तकनीक मिट्टी के स्वास्थ्य, कीटों का पता लगाने और सटीक खेती की तकनीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। उन्नत सिंचाई प्रणाली और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप पानी के उपयोग को कम करने और महिला किसानों के शारीरिक कार्यभार को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को समूह ऋण, प्रशिक्षण और कृषि संसाधनों तक पहुँच से लाभ होता है। तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी इन महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार की खेती का समर्थन करती है। महिलाओं पर बोझ कम करने में मदद करने के लिए बीज बोने वाले, हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर और सोलर ड्रायर जैसे सरल कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। सरकारी पहल मशीनीकृत उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जो महिलाओं के लिए फायदेमंद है। महिला किसान सशक्तिकरण



-प्रियंका सौरभ, रिसर्च स्कॉलर इन पॉलिटिकल साइंस, हरियाणा

परियोजना जैसे एनजीओ और सरकारी कार्यक्रम आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। डिजिटल साक्षरता पहल महिला किसानों को नए फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग कर रही हैं। एआई तकनीक मिट्टी के स्वास्थ्य, कीटों का पता लगाने और सटीक खेती की तकनीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। उन्नत सिंचाई प्रणाली और सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप पानी के उपयोग को कम करने और महिला किसानों के शारीरिक कार्यभार को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को समूह ऋण, प्रशिक्षण और कृषि संसाधनों तक पहुँच से लाभ होता है। तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी इन महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार की खेती का समर्थन करती है। महिलाओं पर बोझ कम करने में मदद करने के लिए बीज बोने वाले, हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर और सोलर ड्रायर जैसे सरल कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। सरकारी पहल मशीनीकृत उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जो महिलाओं के लिए फायदेमंद है। महिला किसान सशक्तिकरण

हलकंग जैसे श्रम-गहन और समय लेने वाले काम सौंपे जाते रहे हैं। हालाँकि, मशीनीकरण उनके कार्यभार को हल्का करने में मदद करता है, जिससे उन्हें अधिक मूल्यवान कृषि गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और सलाहकार सेवाओं सहित डिजिटल उपकरण महिलाओं को अप-टू-डेट बाजार और मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं, जो बेहतर फसल योजना और संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है। कई महिलाओं को ऋण और वित्तीय संसाधनों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। सौभाग्य से, डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मछली विक्रेताओं और किसानों जैसी महिलाओं को स्वतंत्र रूप से लेन-देन करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होती है। महिलाओं को कृषि मशीनरी चलाने के कौशल से लैस करके, ये छोटे-छोटे हस्तक्षेप जड़ जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं और महिलाओं

को खेती में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी तक पहुँच महिलाओं की पारंपरिक बाधाओं को दूर करने और अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की क्षमता को बढ़ाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएँ डिजिटल साक्षरता से जूझती हैं, जो मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता में बाधा डालती हैं। स्मार्टफोन तक सीमित पहुँच और अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन से स्थिति और भी खराब हो गई है। सामाजिक मानदंड निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना जारी रखते हैं। घरेलू स्तर पर निवेश अक्सर उन तकनीकों पर केंद्रित होता है जो मुख्य रूप से पुरुषों को लाभ

पहुँचाती हैं, महिलाओं की अनूठी जरूरतों की उपेक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियाँ और कृषि विस्तार सेवाएँ अक्सर लिंग-विशिष्ट मुद्दों को अनदेखा करती हैं। केवल 13% ग्रामीण महिलाओं के पास जमीन है, इसलिए ऋण और कृषि कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच बहुत सीमित है। कृषि और मत्स्य पालन में मशीनीकरण के बढ़ने से महिलाओं की नौकरियाँ चली गई हैं, जिससे उन्हें लेन-देन करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होती है। महिलाओं को कृषि मशीनरी चलाने के कौशल से लैस करके, ये छोटे-छोटे हस्तक्षेप जड़ जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं और महिलाओं

आँकड़ा 51% है। इस अंतर को पाटने के लिए, सरकार की पहल महिला किसानों के लिए स्मार्टफोन के लिए सब्सिडी दे सकती है।

इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण को शामिल करना महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि किसानों की तकनीक तक पहुँच को सीमित करने में किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है: वित्तीय बाधाएँ या सामाजिक मानदंड? सोलर पंप, डिजिटल भुगतान प्रणाली और माइक्रोलोन जैसे छोटे पैमाने के समाधान तत्काल, उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं। दूसरी ओर, भूमि अधिकार और कृषि तकनीक को अपनाने जैसे व्यापक सुधारों के लिए नीतिगत बदलावों की आवश्यकता होगी और इसमें अधिक समय लगेगा। ओडिशा में, रमिशन शक्तिर पहल ने हजारों महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल लेन-देन में सफलतापूर्वक शिक्षित किया है। हालाँकि, ई-एनएएम प्लेटफॉर्म, जो समाधान डिजिटल कृषि बाजार है, अभी भी भूमि स्वामित्व चुनौतियों के कारण कम महिला भागीदारी से जूझ रहा है। आपको कौन-सी रणनीति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिक प्रभावी लगती है: लक्षित, छोटे पैमाने के हस्तक्षेप या व्यापक प्रणालीगत सुधार? महिलाओं के नेतृत्व वाली कई एग्रीटेक स्टार्टअप इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अपूर्वा बी. के. द्वारा स्थापित कमल किसान छोटे पैमाने के किसानों के लिए कृषि यंत्र कृषि उपकरण प्रदान करता है, जबकि फार्मिजेन जैविक फ़ार्म-टू-टेबल मॉडल के माध्यम से महिला किसानों को सीधे शहर की उपभोक्ताओं से जोड़ता है। क्या सरकार को महिलाओं के नेतृत्व वाली एग्रीटेक उपक्रमों के लिए समर्पित निधि प्रदान करने पर विचार करना चाहिए?

एक सहयोगी दृष्टिकोण जो सरकारी नीतियों, सामुदायिक पहलों और निजी क्षेत्र के नवाचारों को जोड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत में महिला किसानों के पास प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच हो।

स्कोडा कायलैक बेस वर्सेज टॉप वैरियंट: डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स के मामले में कितना अंतर

रिवहन विशेष न्यूज

स्कोडा कायलैक को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है। इसे चार वैरियंट Classic Signature Signature Plus और Prestige में लाया गया है। इसकी भारतीय बाजार में एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख से लेकर 14.40 लाख रुपये तक है। हम यहां पर आपको इसके बेस मॉडल और टॉप मॉडल में क्या-क्या अंतर है और कौन-सा वैरियंट आपके लिए बेहतर हो सकता है इसके बारे में बता रहे हैं।

नई दिल्ली। स्कोडा ने हाल ही में अपनी नई Skoda Kylaq SUV को लॉन्च किया है। इसकी भारतीय बाजार में एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख से लेकर 14.40 लाख रुपये तक है। इसे चार वैरियंट में पेश किया जाता है, जो Classic, Signature, Signature Plus और Prestige है। हम यहां पर आपको इसके बेस वैरियंट Classic और टॉप वैरियंट Prestige में क्या अंतर है और कौन-सा वैरियंट आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं।

1. डिजाइन
फ्रंट: Classic में पिक्सलेटेड LED DRLs और मल्टी-रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट्स को दिया गया है। वहीं, Prestige DRLs का डिजाइन अलग दिया गया है और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स को शामिल किया गया है। दोनों के फ्रंट में LED हेडलाइट्स, LED DRLs, और स्कोडा की बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है और दोनों के डिजाइन में हल्का अंतर है। प्रेस्टीज वैरियंट को बेहतर और प्रीमियम लुक दिया गया है। साइड प्रोफाइल: Classic में कवर के साथ



16-इंच के ब्लैक स्टील व्हील्स दिया गया है, जबकि Prestige में 17 इंच के ड्यूल-टोन एलॉय व्हील्स, डोर हैंडल पर क्रोम एलिमेंट और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है। दोनों वैरियंट के साइड प्रोफाइल में काफी अंतर देखने के लिए मिलता है। दोनों ही वैरियंट में रियर व्युमिर (ORVMs), रूफ रेल्स और बांडी क्लैडिंग पर लगे टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, लेकिन बेस वैरियंट में डोर हैंडल पर क्रोम एलिमेंट और शार्क-फिन एंटीना नहीं दिया गया है। वहीं, टॉप वैरियंट में एलॉय व्हील भी काफी शानदार दिए गए हैं।

रियर: Classic में LED टेल लाइट्स और ब्लैक बम्पर दिया गया है, जबकि Prestige में भी LED टेल लाइट्स और ब्लैक बम्पर मिलते हैं। साथ ही रियर वाइपर और वांशर दिया गया है

और टेल लाइट को जोड़ने के लिए ब्लैक स्ट्रिप भी दी गई है। इसके अलावा रियर बंपर पर सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट भी दी गई है। क्लासिक वैरियंट के मुकाबले प्रेस्टीज वैरियंट के रियर डिजाइन को काफी प्रीमियम लुक दिया गया है, जिसकी वजह से आपको क्लासिक वैरियंट कुछ फीकी लग सकती है।

2. इंटीरियर्स और फीचर्स
Skoda Kylaq के दोनों वैरियंट के केबिन का लेआउट एक जैसा ही है, जिसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन, 2-स्पीक स्टीयरिंग व्हील और AC वेंट्स पर क्रोम सराउंड दिया गया है। बेस मॉडल में टचस्क्रीन नहीं मिलती है, जबकि टॉप मॉडल में 8-इंच की टचस्क्रीन दी गई है। वहीं, जहां बेस में एनालॉग डायल और मल्टी-

इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जबकि टॉप मॉडल में पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। प्रेस्टीज वैरियंट में टच-इनेबल ऑटो AC पेनल और लेदरित सीट अपहोल्स्ट्री दी जा रही है, जबकि क्लासिक वैरियंट में मैनुअल AC और सेमी-लेदर सीट्स दी गई हैं।

3. सेफ्टी फीचर्स
क्लासिक वैरियंट में 6 एयरबैग्स, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है, जबकि प्रेस्टीज वैरियंट में एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स के रूप में रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी दिया गया है, जो क्लासिक में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा, प्रेस्टीज वैरियंट में ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और सिंगल-पेन सनरूफ।

4. इंजन
Skoda Kylaq के सभी वैरियंट में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इसका इंजन 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों वैरियंट में इंजन तो समान ही मिलता है, लेकिन ट्रांसमिशन में अंतर है। क्लासिक वैरियंट को केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में लाया गया है, जबकि प्रेस्टीज वैरियंट को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ-साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में भी पेश किया जाता है।

5. कीमत
क्लासिक वैरियंट की एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख रुपये है, जबकि प्रेस्टीज वैरियंट की 13.35 लाख से 14.40 लाख की एक्स-शोरूम कीमत में आती है।

नए रंग-रूप में लॉन्च हुई होण्डा शाइन 100, नया डिजाइन समेत फीचर्स भी मिले

परिवहन विशेष न्यूज

होंडा ने अपडेटेड 2025 Honda Shine 100 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसके इंजन को OBD-2B के अनुपालन के साथ लाया गया है लेकिन इसके इंजन को पहले की तरह ही रखा गया है। इसे नया डिजाइन और ग्राफिक्स दिया गया है। भारतीय बाजार में यह Hero HF100 Hero Splendor और Bajaj Platina 100 को टक्कर देती है।

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने नई 2025 Honda Shine 100 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसका इंजन अब OBD-2B के अनुपालन के साथ आया है। इसे एक ही वैरियंट में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसे पांच कलर स्क्रीम में पेश किया गया है, जो ब्लैक विद रेड, ब्लैक विद ब्लू, ब्लैक विद ऑरेंज, ब्लैक विद ग्रे और ब्लैक विद ग्रीन है। इसके साथ ही 2025 Honda Shine 100 के बांडी पैन को नए रिफ्रेश ग्राफिक्स के साथ लेकर आया गया है। इसे अपडेट मिलने बाद कंपनी को इसकी बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।

इंजन
2025 Honda Shine 100 में वही पुराने 98.98 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 7.38 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब इसका इंजन OBD-2B का अनुपालन करता है। इसके इंजन को पहले की तरह ही 4-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

कीमत



नई Honda Shine 100 को नई कीमत में लॉन्च किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 68,767 रुपये है, जो पहले से 1,867 रुपये महंगी है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hero HF100, Hero Splendor और Bajaj Platina 100 से देखने के लिए मिलता है।

अंडरनिपिंग
अपडेटेड Honda Shine 100 में पहले की तरह ही टेलिस्कोपिक फोर्क और ट्विन शाक

एब्जॉर्बर को दिया गया है। इसे पहले की तरह ही ट्यूब वाले टायर के साथ 17 इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें ब्रेकिंग के लिए CBS (कंबाईड ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ 130 mm फ्रंट और 110 mm रियर ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसमें 786 mm की सुलभ सीट ऊंचाई, 168mm का ग्राउंड क्लियरेंस और सिर्फ 99 kg का वजन है।

फीचर्स
2025 Honda Shine 100 में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर,

ओडोमीटर और फ्यूल गेज सहित नियमित रीडआउट की जानकारी मिलती है। बाइक में सेफ्टी को ध्यान रखते हुए साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर को शामिल किया गया है।

यह हमेशा से ही लोगों के बीच पॉपुलर रही है। वहीं, यह किफायती होने के साथ ही काफी कम मेंटेन वाली बाइक रही है। अब यह OBD-2B अपडेट के साथ पर्यावरण के अनुकूल हो गई है। वहीं, इसे नए कलर मिलने से संभावित खरीदारों के बीच इसकी अपील भी बढ़ सकती है।

मारुति सुजुकी की गाड़ियां अप्रैल से और हो जाएंगी महंगी, कीमतों में होगा 4% तक इजाफा



परिवहन विशेष न्यूज

अप्रैल 2025 से मारुति सुजुकी की गाड़ियां और महंगी होने जा रही हैं। Maruti अपनी गाड़ियों की कीमत में फिर से 4 फीसद तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी ने कीमतों को बढ़ाने के पीछे का कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत और ऑपरेशनल खर्चों को बताया है। कीमतों का इजाफा मॉडल के आधार पर होगा।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की गाड़ियां और महंगी होने वाली हैं। कंपनी अप्रैल 2025 से अपनी गाड़ियों की कीमत को फिर से बढ़ाने जा रही है। इस बार भी कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमत में 4% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने नियामकीय फाइलिंग के दौरान इसके बारे में बताया। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि गाड़ियों की कीमतों में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है और यह मॉडल पर अलग-अलग होगी।

कंपनी ने बताया ये कारण
मारुति सुजुकी ने गाड़ियों की कीमत को बढ़ाने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि कंपनी लगातार लागतों को अनुकूलित करने और अपने ग्राहकों पर प्रभाव को कम करने का प्रयास करती है, लेकिन बढ़ती हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार में डालने की

आवश्यकता हो सकती है। मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा है कि कार की कीमत बढ़ाने का फैसला, कच्चे माल की बढ़ती लागत और ऑपरेशनल खर्चों के कारण लिया गया है। कंपनी की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन मॉडलों की कीमतों से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। मारुती भारतीय बाजार में एंटी-लेवल हैचबैक से लेकर प्रीमियम एसयूवी तक की गाड़ियों को पेश करती है।

2025 में कब-कब बढ़ी कीमत
कंपनी इससे पहले भी 4% की बढ़ोतरी कर चुकी है। इसकी घोषणा कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में की गई थी और उसे जनवरी में लागू किया गया था। इस दौरान अलग-अलग मॉडल की कीमतों में 1,500 रुपये से 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसकी तरह से फरवरी 2025 में भी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी।

मारुति सुजुकी भारत में ये मॉडल करती है पेश

देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर मारुति सुजुकी हाल के समय में भारतीय बाजार में Alto K10 to the S-Presso, Eeco, Celerio, Wagon R, Ignis, Swift, Baleno, Dzire, Fronx, Brezza, Ertiga, Ciaz, Grand Vitara, XL6, Jimny और Invicto को ऑफर करती है।

हुंडई ग्रैंड 10 एनआईओएस का नया कॉर्पोरेट वैरियंट लॉन्च,

परिवहन विशेष न्यूज

साउथ कोरियाई कार निर्माता Hyundai Motors की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन Cars And SUVs को ऑफर किया जाता है। Hyundai Motor India की ओर से हाल में ही हैचबैक कार के तौर पर ऑफर की जाने वाली Grand i10 Nios का नया Corporate Variant लॉन्च किया गया है। इसे किस कीमत पर और किन खुबियों के साथ लाया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कई बेहतरीन कारों और एसयूवी की बिक्री करने वाली साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai Motors ने हैचबैक कार Grand i10 Nios का नया Corporate Variant लॉन्च कर दिया है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि इस नए वैरियंट में कंपनी की ओर से क्या खुबियां दी गई हैं। साथ ही इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Hyundai Grand i10 Nios का Corporate Variant लॉन्च
हुंडई मोटर इंडिया की ओर से भारतीय बाजार में ऑफर की जाने वाली हैचबैक कार आई-10 का नया कॉर्पोरेट वैरियंट लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इसमें कई बेहतरीन खुबियों को भी दिया गया है। इस वैरियंट के जरिए कंपनी युवाओं को लुभाने की

तैयारी कर रही है।
कैसे हैं फीचर्स
हुंडई ने ग्रैंड आई-10 नियोस के कॉर्पोरेट वैरियंट में 17.14 सेमी टचस्क्रीन दिया है। इसके साथ गाड़ी में ड्यूल टोन स्टाइल के 15 इंच व्हील्स, छह एयरबैग, 30 से ज्यादा सेफ्टी फीचर, ड्यूल टोन ग्रे इंटीरियर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फुटवेल लाइट, फ्रंट रूम लैंप, स्टेयरिंग व्हील मारुटिड कंट्रोल, रियर एसी वेंट, पैसेंजर वेनिटी मिरर, टीपीएमएस, एबीएस, ईबीडी, एलईडी डीआरएल, टेलगेट पर कॉर्पोरेट बैजिंग को दिया गया है। इस कार में कुल सात मोनोटोन रंगों का विकल्प दिया गया है। जिसमें अमंजन ग्रे को नए रंग के तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें Atlas White, Typhoon Silver, Titan Grey, Teal Blue, Fiery Red, Spark Green जैसे रंग मिलेंगे।

कितना दमदार इंजन
हुंडई ने आई-10 नियोस में 1.2 लीटर Kappa पेट्रोल इंजन दिया है। जिसके साथ पांच स्पीड मैनुअल और स्मार्ट ऑटो एमटी ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है।

फिनो है कीमत
हुंडई ने ग्रैंड आई-10 नियोस के कॉर्पोरेट वैरियंट को 6.93 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। वहीं इसके एमटी वैरियंट की एक्स शोरूम कीमत को 7.58 लाख रुपये रखा गया है।

महिंद्रा XUV700 की ऑल-ब्लैक एडिशन में एंटी, पैनोरमिक सनरूफ समेत ADAS जैसे फीचर्स से है लैस

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा XUV700 का ऑल-ब्लैक एडिशन लॉन्च हो गया है। इसे Ebony Edition के रूप में लॉन्च किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.64 लाख रुपये है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर को ऑल-ब्लैक थीम दिया गया है। इसके डिजाइन को रेगुलर XUV700 की तरह ही रखा गया है। इसमें वो सभी फीचर्स मिलते हैं जो XUV700 के टॉप-स्पेक AX7 और AX7 L वैरियंट में दिए जाते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में महिंद्रा ऑटो Mahindra XUV700 को पेश करती है। अब कंपनी ने Mahindra XUV700 Ebony Edition को लॉन्च कर दिया है। इसमें ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर थीम दी गई है, लेकिन इसके डिजाइन को रेगुलर SUV के जैसा ही रखा गया है। आइए जानते हैं कि Mahindra XUV700 के नए एडिशन में क्या नया दिया गया है।

कीमत (Price)
वैरियंट
रेगुलर XUV700
XUV700 Ebony
कीमतों में अंतर
AX7 टर्बो-पेट्रोल MT
19.49 लाख रुपये
19.64 लाख रुपये

15,000 रुपये
AX7 टर्बो-पेट्रोल AT
20.99 लाख रुपये
21.14 लाख रुपये
15,000 रुपये
AX7 डीजल MT
19.99 लाख रुपये
20.14 लाख रुपये
15,000 रुपये
AX7 डीजल AT
21.69 लाख रुपये
21.79 लाख रुपये
10,000 रुपये
AX7 L टर्बो-पेट्रोल AT
23.19 लाख रुपये
23.34 लाख रुपये
15,000 रुपये
AX7 L डीजल MT
22.24 लाख रुपये
22.39 लाख रुपये
15,000 रुपये
AX7 L डीजल AT
23.99 लाख रुपये
24.14 लाख रुपये
10,000 रुपये
Mahindra XUV700 Ebony Edition को इसके टॉप-स्पेक AX7 और AX7 L वैरियंट के 7-सीटर वर्जन पर आधारित है। इसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिया जा रहा है।



क्या मिला नया ?

Mahindra XUV700 Ebony Edition को सिर्फ ब्लैक-आउट वर्जन में लाया गया है, इसलिए इसका बाहरी डिजाइन रेगुलर मॉडल के जैसा ही है। इसके दोनों वर्जन में हेडलाइट्स, LED DRLs, LED फॉग लैंप और टेल लाइट्स सामान ही दिए गए हैं।

Ebony Edition में ब्लैक-आउट 18-इंच एलॉय व्हील्स, ग्रिल पर ब्लैक इंस्टैंड, ब्लैक रूफ रेल्स और आउटसाइड रियर व्युमिर (ORVMs), फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स पर भी सिल्वर फिनिश और डोर हैंडल पर क्रोम एक्सटेंड दिया गया है। इसे रेगुलर वैरियंट से अलग दिखाने के लिए ORVMs के नीचे फ्रंट

डोर पर 'Ebony' बैज दिया गया है। Ebony Edition के केबिन को रेगुलर वैरियंट के जैसा ही दिया गया है। इसमें एक्सटीरियर की तरह ही इंटीरियर में भी ऑल-ब्लैक थीम दी गई है। इसमें ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड, सीट और डोर पैड पर ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री और डार्क क्रोम AC वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा लाइट ग्रे हेडलाइनर, डैशबोर्ड और डोर पैड पर सिल्वर एक्सटेंड को शामिल किया गया है। वहीं, अंदर के डोर हैंडल और सेंटर कंसोल को पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है।

फीचर्स (Features And Safety)
फीचर्स के मामले में दोनों में ही वह सभी

फीचर्स दिए गए हैं, जो Mahindra XUV700 के AX7 और AX7 L वैरियंट में मिलते हैं। इसमें 0.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल-जोन ऑटो AC, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट वॉशरलेस फोन चार्जर, 12-स्पीकर वाला सोनी ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और वाइपर दिया गया है।

इसमें लोगों की सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

(TPMS), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सहित एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेड सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन (Powertrain Options)
इंजन
2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
2.2-लीटर डीजल
पावर
200 PS
Up to 185 PS
टॉर्क
380 Nm
450 Nm
ट्रांसमिशन
6-स्पीड MT/6-स्पीड AT
6-स्पीड MT/6-स्पीड AT
ड्राइवट्रैन
FWD
FWD/AWD
Mahindra XUV700 दो इंजन ऑप्शन के साथ पेश की जाती है। इसके Ebony Edition को केवल FWD ड्राइवट्रैन में पेश किया गया है।

प्रतिद्वंद्वी (Rivals)
भारतीय बाजार में Mahindra XUV700 Ebony Edition का मुकाबला Tata Safari, MG Hector Plus और Hyundai Alcazar जैसी गाड़ियों से देखने के लिए मिलेगा।

क्या है एसआईएफ? म्यूचुअल फंड की स्कीम से कैसे है ये अलग; जानें इससे जुड़ी सभी बातें

परिवहन विशेष न्यूज

एसआईएफ को Specialised Investment Fund भी कहा जाता है। एसआईएफ म्यूचुअल फंड की मौजूदा स्कीम और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMSes) के बीच आता है। इसकी इन्वेस्टमेंट एप्रोच और स्ट्रेटजी बाकी स्कीम से काफी अलग है। इस स्कीम के तहत निवेशकों को 25 फीसदी तक रिटर्न मिल जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं।

नई दिल्ली। सेबी (SEBI) ने पिछले साल इस एसेट क्लास को अनुमति दी थी। एसआईएफ को उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो हाई रिस्क उठा सकते हैं। ये मौजूदा म्यूचुअल फंड की स्कीम से काफी अलग है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) के तहत निवेशकों को एडवान्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी (Advanced Investment Strategy) का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। एसआईएफ (SIF) के तहत अलग तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी (Investment Strategy) और एप्रोच (Approach) अपनाने जाती है। एसआईएफ के तहत निवेशकों को अनुमानित 25 फीसदी तक रिटर्न मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसमें न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपये रखी गई है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड की कई



स्कीम में न्यूनतम निवेश राशि 100 रुपये है। वहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (Portfolio Management Services) में कम से कम 50 लाख रुपये और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (Alternative Investment Funds) में कम से कम 1 करोड़ रुपये निवेश करने होते हैं।

Specialised Investment Fund क्या है?
स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (Specialised Investment Fund) एक एसेट क्लास (Asset Class) है। ये म्यूचुअल फंड की मौजूदा स्कीम और पीएमएस के बीच में आता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से निवेश शुरू

कर सकते हैं, वहीं पीएमएस के तहत न्यूनतम 50 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते हैं। जबकि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड तहत न्यूनतम 10 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) के तहत न्यूनतम 1 करोड़ रुपये निवेश करने होते हैं। शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली सेबी ने ये देखा कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड की स्कीम के बीच कोई भी स्कीम उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण निवेशक ज्यादा अमाउंट वाली स्कीम में निवेश करते हैं और इससे पैसा डूबने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है।

SIF में तीन तरह के मिलते हैं फंड
स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के तहत तीन

तरह के फंड ऑफर किए जाते हैं। इनमें शॉर्ट फंड, एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड और सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड का ऑप्शन मिलता है। शॉर्ट फंड- इस फंड के तहत आपका पैसा 80 फीसदी तक इक्विटी (equity) और 25 फीसदी तक शॉर्ट पोजिशन कर सकते हैं। एक्स-टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड के तहत आपका 65 फीसदी पैसा टॉप 100 से बाहर की गई कंपनियों पर लगाया जाता है। 25 फीसदी तक पैसा का शॉर्ट पोजिशन कर सकते हैं। सेक्टर रोटेशन लॉन्ग-शॉर्ट फंड के तहत आपका पैसा 4 सेक्टरों में कम से कम 80 फीसदी तक निवेश होता है। वहीं इसके तहत भी आपको 25 फीसदी तक शॉर्ट पोजिशन का ऑप्शन मिलता है।

भारत-चीन के व्यापार में अंतिम तिमाही में वृद्धि, कई विकसित देशों में व्यापार संकुचन: रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

विश्व निकाय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत व चीन ने 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में औसत से बेहतर व्यापार विस्तार किया। रिपोर्ट में हालांकि, आगामी तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की संभावना की चेतावनी दी है। इस बारे में विस्तार से जानें।

विश्व निकाय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत व चीन ने 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में औसत से बेहतर व्यापार विस्तार किया। रिपोर्ट में हालांकि, आगामी तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की चेतावनी दी है। इसके मुताबिक, विकासशील देशों, खासकर चीन व भारत में जहां व्यापार विस्तार हुआ, वहीं कई विकसित देशों में व्यापार संकुचन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (यूएनसीटीएडी) द्वारा नवीनतम वैश्विक व्यापार अपडेट में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक व्यापार लगभग 1,200 अरब डॉलर यानी नौ प्रतिशत के विस्तार के साथ 33,000 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह अपडेट मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों को कवर करता है। इसमें कहा गया है कि चीन और भारत ने 2024 की चौथी तिमाही में मजबूत व्यापार गति देखी, जबकि अमेरिका एक प्रमुख चालक बना रहा। 2024 की चौथी तिमाही में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक व्यापार ने मिश्रित रुझान दिखाए। चीन, भारत के व्यापार में, विशेष रूप



से निर्यात में वृद्धि जारी रही।

व्यापार में 8% की तिमाही आयात वृद्धि
अमेरिका में, 2024 की चौथी तिमाही में आयात वृद्धि ठीक रही, वहीं निर्यात वृद्धि घट गई। भारत ने 2024 की चौथी तिमाही में माल व्यापार में तिमाही आधार पर 8% और वार्षिक आधार पर 6% आयात वृद्धि दर्ज की। तिमाही निर्यात 7% और सालाना 2% निर्यात वृद्धि रही।

भारत-द.अफ्रीका के लिए सेवा व्यापार मजबूत

2024 की चौथी तिमाही में सेवा व्यापार में वृद्धि जारी रही। यह दर्शाता है कि सेवा व्यापार में सकारात्मक रुझान अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिर हो सकता है। भारत व दक्षिण अफ्रीका के लिए सेवा व्यापार में वृद्धि मजबूत रही। वार्षिक आधार पर कई सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सेवा व्यापार वृद्धि दहाई अंक के आंकड़े तक पहुंच गई।

'भारत को एफटीए के तहत ईयू से चिकित्सा उपकरणों पर करनी चाहिए विशेष छूट की मांग', वैश्विक थिंक टैंक का सुझाव

'थिंक टैंक जीटीआरआई ने सुझाव दिया कि भारत को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय संघ से चिकित्सा उपकरणों पर कुछ विशेष छूट की मांग करनी चाहिए, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। भारत को तब ही टैरिफ कम करना चाहिए, जब यूरोपीय संघ अपने गैर-जरूरी अवरोध हटाए।

नई दिल्ली। भारत को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत यूरोपीय संघ (ईयू) से चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में कुछ विशेष छूट की मांग करनी चाहिए। इससे भारत अपने निर्यात को बढ़ावा दे सकेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने रविवार को यह सुझाव दिया। भारत अधिकांश चिकित्सा उपकरणों पर 0 से 10 फीसदी तक टैरिफ लगाता है। अगर भारत बिना यूरोपीय संघ के नियामक चुनौतियों को हल किए चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ कम करता है, तो इससे यूरोपीय संघ से आयात बढ़ सकता है, लेकिन निर्यात कम हो सकता है। जीटीआरआई ने कहा, एक समान और निष्पक्ष व्यापार सौदा करने के लिए भारत को बदले में कुछ छूट की मांग करनी चाहिए। भारत को चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ तभी कम करना चाहिए, जब यूरोपीय संघ अपने गैर-जरूरी टैरिफ के अवरोधों को हटाए। चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत-यूरोपीय संघ वार्ता असमान है। यूरोपीय संघ जहां चिकित्सा उपकरणों पर भारत से शून्य टैरिफ की मांग करता है, वहीं दूसरी तरफ वह उच्च नियामक अवरोध बनाए



रखा है, जो भारत के निर्यात को यूरोपीय संघ के बाजारों के लिए कठिन बना देता है। चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत-ईयू एफटीए वार्ता असमान है। जहां एक तरफ यूरोपीय संघ भारत से चिकित्सा उपकरणों पर शून्य शुल्क की मांग करता है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय उत्पादों को अपने बाजार में

बेचने में मुश्किलें पैदा करता है। इससे भारत को यूरोपीय संघ के बाजार में अपने निर्यात को बढ़ाने में दिक्कत होती है।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क को दूर शून्य है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में प्रवेश की लागत बहुत

अधिक है, क्योंकि वहां के नियामक ढांचे में कड़ी शर्तें हैं। उन्होंने कहा, यूरोपीय संघ में निर्यात करना अब और कठिन हो गया है, क्योंकि उसने मेडिसिन डिवाइस डिरेक्टिव (ईयू-एमडीडी) को बदलकर मेडिकल डिवाइस रूल्स (ईयू-एमडीआर) लागू किया है। ये नियम ज्यादा सख्त हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 15 अरब डॉलर का उछाल, तीन साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी



विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग चार महीने तक गिरावट रही और हाल ही में यह 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें कुछ सप्ताह बढ़त और कुछ सप्ताह गिरावट देखी गई।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबर्दस्त उछाल आया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह 15.267 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 653.966 अरब डॉलर हो गया है। यह बीते तीन साल में एक सप्ताह में हुई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है।

बीते चार महीने रहा गिरावट का दौर

विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग चार

महीने तक गिरावट रही और हाल ही में यह 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें कुछ सप्ताह बढ़त और कुछ सप्ताह गिरावट देखी गई। इससे पहले बीते साल सितंबर में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने अभी तक के सबसे उच्च स्तर 704.89 अरब डॉलर के आंकड़े को छुआ था, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट रही और फिलहाल यह अपने उस उच्चतम स्तर से सात प्रतिशत नीचे है।

74 अरब डॉलर का सोने का भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की वजह रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप को माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य रुपये में तेज गिरावट को रोकना है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रुपया

अब अमेरिकी डॉलर की तुलना में सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया है। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि भारत की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए), जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, 557.282 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सोने का भंडार 74.325 अरब अमेरिकी डॉलर है।

अनुमान के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 10-11 महीने के अनुमानित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। 2023 में, भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 58 अरब डॉलर जोड़े, जबकि 2022 में इसमें 71 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। 2024 में, भंडार में 20 अरब डॉलर से थोड़ा ज्यादा की वृद्धि हुई।

ट्रंप ने सरकार को छह महीने के वित्तपोषण वाले विधेयक पर किए हस्ताक्षर, शटडाउन का टला खतरा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर के अंत तक सरकार को वित्तपोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे फिलहाल सरकारी शटडाउन का खतरा टल गया है और कांग्रेस में चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर के अंत तक सरकार को वित्तपोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे फिलहाल सरकारी शटडाउन का खतरा टल गया है और कांग्रेस में चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया है। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स के बीच भी मतविभाजन दिख रहा था। व्हाइट हाउस के प्रधान उप प्रेस सचिव हैरिसन फोल्ड्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रम्प ने शनिवार को सतत प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।

इस विधेयक में सरकारी वित्तपोषण को मोटे तौर पर जो बाइडन के राष्ट्रपतिवत् काल के दौरान निर्धारित स्तर पर ही रखा गया है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में गैर-रक्षा व्यय में लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती की गई है तथा रक्षा व्यय में लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की गई है, जो कि लगभग 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के शीर्ष व्यय स्तर को देखते हुए मामूली परिवर्तन है। सीनेट ने शुक्रवार को 54-46 पार्टी लाइन वोट से विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें सीनेट डेमोक्रेटिक कांसंस के 10 सदस्यों ने अपनी पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद विधेयक को पारित करने में मदद की।

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला: 12 करोड़ की धोखाधड़ी में कपिल देधिया गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई

ईओडब्ल्यू ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी के मामले में वांछित आरोपी कपिल देधिया को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में ईओडब्ल्यू ने बताया कि देधिया को कल वडोदरा में एक समन्वित अभियान के तहत पकड़ा गया और आज मुंबई लाया गया।

मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी के मामले में वांछित आरोपी कपिल देधिया को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में ईओडब्ल्यू ने बताया कि देधिया को कल वडोदरा में एक समन्वित अभियान के तहत पकड़ा गया और आज मुंबई लाया गया। गिरफ्तारी के बाद, कपिल देधिया को शनिवार सुबह 11:30 बजे अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 19 मार्च, 2025 तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

जांच में हुआ ये खुलासा: ईओडब्ल्यू ने जांच को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अब तक के जांच से यह खुलासा हुआ है कि कपिल देधिया के खाते में कुल 12 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, जो बैंक से गलत तरीके से निकाले गए धन का हिस्सा थे। यह राशि दो मुख्य स्रोतों से आई थी। इसमें एक हिस्सा धर्मेश रियल्टी के बिल्डर धर्मेश पौन से प्राप्त हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा अरुणाचलम नामक व्यक्ति द्वारा ट्रान्सफर किया गया था, जो मामले में एक और वांछित आरोपी है। इसके अतिरिक्त, उसे कथित तौर पर हितेश मेहता से भी धन प्राप्त हुआ था।

अभी चल रही मामले की जांच: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा मामले की जांच अब भी जारी है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच से और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है और गड़बड़ी में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।

क्या है मामला?: मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक, लेखा प्रमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ 122 करोड़ रुपये के गबन का मामला दर्ज किया था। मामले को आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया था। सीनेट डेमोक्रेट्स ने कई दिनों तक इस बात पर बहस की कि क्या शटडाउन बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सदन में रिपब्लिकन ने उनके इनपुट के बिना ही खर्च के उपाय का मसौदा तैयार किया और उसे पारित कर दिया। डेमोक्रेट्स ने कहा कि यह कानून स्वास्थ्य सेवा, आवास और अन्य प्राथमिकताओं को कमतर तरीके से आंकता है और ट्रम्प को संघीय खर्च को पुनर्निर्देशित करने की पूरी छूट देता है, और उनका प्रशासन और सरकारी दक्षता विभाग कांग्रेस की ओर से स्वीकृत

एजेंसियों और कार्यक्रमों को तेजी से खत्म कर रहा है।

अंत में, अधिकांश डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने यह निर्णय लिया कि सरकार को बंद करना वित्त पोषण विधेयक को पारित करने से भी अधिक बुरा होगा। सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता केव शूम्पर ने कहा कि शटडाउन से ट्रम्प प्रशासन को संपूर्ण एजेंसियों, कार्यक्रमों और कर्मियों को गैर-आवश्यक मानने की क्षमता मिल जाएगी, और कर्मचारियों को बिना किसी वादे के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा कि उन्हें

फिर से काम पर रखा जाएगा।

शूम्पर ने कहा, शटडाउन DOGE को बिना नियंत्रण से काम करने की अनुमति देगा। डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं को बहुत तेज गति से नष्ट करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सप्ताह के शुरू में सदन के माध्यम से फंडिंग बिल का पारित होना ट्रम्प और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन के लिए एक जीत है। वे रिपब्लिकन को एक साथ रखने और डेमोक्रेट्स के समर्थन के बिना बिल को पारित करने में कामयाब रहे।

बैलों से खेती: छोटे व सीमांत किसानों को प्रोत्साहन

सुनील कुमार महला

राजस्थान सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कुछ समय पहले ही एक शानदार व अच्छा फैसला आया है। पाठकों को बताता चलू कि सरकार के इस फैसले के अनुसार अब राजस्थान सरकार से खेती करने वाले को 30 हजार रुपए वार्षिक सहायता देगी। कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल बैलों के संरक्षण को दिशा में एक अहम-और महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संभल भी मिल सकेगा। आज के इस आधुनिक दौर में जब तक-बाड़ी आधुनिक कृषि यंत्रों ट्रेक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम आदि और तकनीक से की जाने लगी है, उस दौर में खेती के पारंपरिक तौर-तरीकों पर एकबार पुनः ध्यान केंद्रित किए जाने से आर्थिक व वैज्ञानिक खेती को भी बढ़ावा मिल सकेगा। पाठकों को बताता चलू कि राजस्थान के नगौर जिले में बैल जन्मादा पाए जाते हैं तथा यहां के बैल अपनी ताकत, तेज रफ्तार, और सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन वर्तमान में इन बैलों की पहले के जमाने की भांति अब खेतों में उतनी वैल्यू नहीं रही है, क्यों कि लगातार बढ़ते शहरीकरण, कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों व तकनीक के प्रयोग से तथा लगातार कम होते चरागाहों व वन्य क्षेत्र में पहले की तुलना में कमी के कारण, किसान भी बैल पालने से अब कतराने लगे हैं, ऐसे में वर्तमान में राजस्थान सरकार की ओर से जो खबर आई है, राजस्थान के किसानों में पशुपालन (बैलों) के प्रति जोश व मोह पैदा करेगी। कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के इस कदम से रामदेव जी पशु मेला, तेजाजी का मेला (परबतर उपखंड), बलदेवरा मजी का मेला (मेड़ता सिटी उपखंड) के अस्तित्व को भी बल मिलेगा, क्यों कि ये मेले बैलों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अब इस

सरकारी योजना से उम्मीद जगी है कि बैलों की मांग बढ़ेगी और पशु मेले फिर से जीवंत हो सकते हैं। इससे पारंपरिक पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों को नई आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी। सरकार के निर्णय से कृषि यंत्रों से होने वाले प्रदूषण पर भी कुछ हद तक लगाम लग सकेगी और किसान परंपरागत जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे। कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ वर्षों में बैलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, सरकार को इस योजना के बाद बैलों से खेती पुनर्जीवित हो सकेगी। गोपालन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बैलों के पालन-पोषण पर होने वाले खर्च में इस प्रोत्साहन राशि से काफी सहयोग मिल सकेगा। इस योजना से छोटे किसान रासायनिक उर्वरकों की बजाय खेती में प्राकृतिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि अब तक आर्थिक समस्याओं के चलते छोटे बड़ों को निराश्रित छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ये उपयोगी साबित हो सकेगा। खेती की लागत में भी इससे कमी आएगी, क्यों कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती पर किसानों का काफी खर्च हो जाता है। पारंपरिक खेती को बढ़ावा मिलने से मिट्टी की उर्वरता तो बनी ही रहेगी साथ ही साथ इससे पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि इस संबंध में कुछ समय पहले ही कृषि विभाग के कृषि आयुक्त ने बजट घोषणा की पालना में एक आदेश जारी कर बैलों से खेती करने वाले किसानों की जानकारी हर जिले से मांगी गई है। जानकारी के अनुसार जिलों में बैलों से खेती करने वाले किसानों की जानकारी एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, ताकि अधिकारिक लोगों को सरकार की इस शानदार योजना का फायदा मिल सके। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यह प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। यहां यह भी गौरतलब है कि बैलों से खेती पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के साथ

ही बैलों और गायों से मिलने वाले गोबर का उपयोग करने के लिए किसानों द्वारा गोबर गैस प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी का प्रावधान है। इस संबंध में जिला कृषि विभाग कार्यालय या नजदीकी कृषि सेवा केंद्र में सम्पर्क किया जा सकता है। वास्तव में यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि यह योजना प्रामाणिक और जैविक खेती-किसानी को भी एक नया जीवन प्रदान करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। योजना से कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा और यह योजना कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ व मजबूत बनाएगी। जैविक खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। ऊपर बता चुका हूँ कि आज बढ़ते खर्च, शहरीकरण, आधुनिकता की आड़ में राजस्थान के अधिकतर किसानों ने बैलों को त्याग दिया है। सिंचाई के साधनों से वंचित किसानों ने भी आधुनिक उपकरणों का सहारा लेकर बैलों की उपयोगिता को भुला सा दिया है। शायद यही कारण भी है कि पिछले कुछ समय से पशुधन की संख्या में भी तेजी से गिरावट आई है। यह योजना इस समस्या का समाधान बखूबी कर सकती है और बैलों के महत्व को फिर से स्थापित कर सकती है। बहरहाल, कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान सरकार ने जो योजना राजस्थान में शुरू की है, वह यदि पहाड़ी क्षेत्रों में भी छोटे किसानों के लिए शुरू की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों की तकदीर बदल सकती है, क्यों कि पहाड़ों में (विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में) अक्सर कृषि जोते-एक-दो हेक्टेयर से छोटी होती है। आज हिमाचल प्रदेश में पाँवर टिलर को 50 फीसदी तक सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। पावर टिलर जैसे यंत्र हमारे पर्यावरण को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, क्यों कि ये धुंआ छोड़ते हैं और शोर भी करते हैं और इन पर लागत भी कम नहीं है। वैसे भी गरीब किसानों के लिए पावर टिलर खरीदना एक बड़ी बात है। ऐसे में पूरे भारतवर्ष में ही जो कृषि जोते एक या दो हेक्टेयर से छोटे हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर होने का मार्ग बैलों से

खेती के माध्यम से ही निकल सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि किसी पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह और भी ज्यादा जरूरी इसलिए है, क्योंकि यहां की 80 से 85 फीसदी जोते एक हेक्टेयर से भी छोटे हैं, इनमें से कुछ तो एक एकड़ से भी छोटे हैं। यदि हम यहां आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में औसत जोत का आकार 0.95 हेक्टेयर है। राज्य में 88.86 प्रतिशत किसान सीमांत और लघु वर्ग के हैं। इन किसानों के पास बड़े जाने वाली जोत का 55.93 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में 10.84 प्रतिशत किसान मध्यम श्रेणी के हैं। केवल 0.30 प्रतिशत किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र 55.673 लाख हेक्टेयर है। राज्य में 64 प्रतिशत भूमि जोत एक हेक्टेयर (सीमांत) से कम है। राज्य में 21 प्रतिशत भूमि जोत 1-2 हेक्टेयर के बीच है। राज्य में 70 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी कृषि भूमि का औसत आकार 0.95 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तराखंड में लघु और सीमांत जोतों का हिस्सा ज्यादा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में सीमांत, छोटी, और बड़ी कृषि जोतों का क्षेत्रफल क्रमशः 36.23%, 27.6%, और 36.16% है। बहरहाल, यहां यह ठीक है कि बड़ी जोत वाले किसानों के लिए बैलों से कृषि कार्य करना काफी जोत वाले, किन्तु छोटी व सीमांत जोत वाले किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि खेती-किसानी यदि आत्मनिर्भर होगी तो किसानों के लिए कर्ज से मुक्ति का रास्ता भी बनेगा, जिसके कारण कृषक आत्महत्याओं पर भी रोक लगेंगी। आज जरूरत इस बात की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी छोटे व सीमांत किसानों को ऐसी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि कृषि घाटे का सौदा न रहे और पहाड़ी क्षेत्रों के किसान भी कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रधान (केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का पिता) का निधन

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूवनेश्वर: केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के पिता देवेन्द्र प्रधान का निधन। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 83 वर्ष थी। देवेन्द्र प्रधान वाजपेयी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देवेन्द्र प्रधान को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की

और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस समय मोदी के साथ मौजूद थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेदारियां संभालकर अपने प्रशासनिक कौशल का भी प्रदर्शन किया है। अपने शोक संदेश में श्री पटनायक ने कहा कि स्वर्गीय डॉ. प्रधान को उनके अद्वितीय संगठनात्मक कौशल और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए याद किया जाएगा।

राजनीतिक व्यक्ति और लोकप्रिय राजनेता खो दिया है। नवीन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय डॉ. प्रधान को गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री पटनायक ने कहा कि स्वर्गीय डॉ. प्रधान को उनके अद्वितीय संगठनात्मक कौशल और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए याद किया जाएगा।



केन्द्र सरकार नहीं जानती कैसे हुई थी संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर की मृत्यु:- नरेश गुणपाल

हिसार/चण्डीगढ़/नई दिल्ली 17 मार्च

आरटीआई धर्मदेव नरेश गुणपाल द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर की मृत्यु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी मांगी गई थी, जानकारी मुझे या करवाने की रिश्ती में उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है कि केंद्र सरकार के पास 2005 में संविधान निर्माता की जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो कि देश के लिए एक विडम्बना है। उन्होंने कहा कि बिंदु नंबर एक में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की मृत्यु का स्थान और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी के बारे में जानकारी मांगी थी, बिंदु नंबर दो में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की मृत्यु उपराल अन्का पोस्टमार्टम करवाने के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम की सत्यापित कॉपी की मांग की गई थी, बिंदु नंबर तीन में आवेदक ने संविधान निर्माता की मृत्यु के बारे में जानकारी मांगी थी कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी या फिर उनकी रखा तथा उनकी मृत्यु किस तारीख को हुई, बिंदु नंबर चार में आवेदक ने संविधान निर्माता की मौत से सम्बन्धित जॉब के बारे में पूछा गया था कि उनकी मौत की जॉब किसी

आयोन-संविदा द्वारा की गई थी, मौत की जॉब की रिश्ती में जॉब की सत्यापित कॉपी की मांग की गई थी। बिंदु नंबर पाँच में आवेदक द्वारा संविधान निर्माता की जन्म तारीख एवं जन्म स्थान के बारे में जानकारी मांगी गई थी। लेकिन एक भी बिंदु की जानकारी का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के उप सचिव (3) तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर की मृत्यु से संबंधित जानकारी के आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत आवश्यक कार्यावाही हेतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार जनपथ नई दिल्ली, गोडन लोक सूचना अधिकारी डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 15 जनपथ नई दिल्ली एवं पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय आई. पी. स्टेट नई दिल्ली को स्थानांतरण कर दी गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार जनपथ नई दिल्ली के सहायक निदेशक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि मांगी गई सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अभिलेखागार में डॉ.



भीमराव अम्बेडकर से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध है और यह एक गहन शोध का विषय है अतः आप इस विषय पर शोध के लिए यहाँ किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान आ सकते हैं। आपको पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, 1993 के अंतर्गत सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि निदेशक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 15 जनपथ नई दिल्ली द्वारा जवाब दिया गया कि इस कार्यलय में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यालय पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन आठवां तल एच० एस० ग्री० बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय इंदरप्रस्थ स्टेट नई दिल्ली के सहायक जन सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय आई. पी. स्टेट नई दिल्ली द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत आयुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी उत्तरी जिला सिविल लाइन्स दिल्ली को स्थानांतरित की गई, लेकिन जन सूचना अधिकारी एवं अधिकृत आयुक्त पुलिस उत्तरी जिला सिविल लाइन्स दिल्ली ने भी आवेदक के आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत आयुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी नई दिल्ली जिला पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दी गई। उन्होंने कहा कि आयुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी नई दिल्ली जिला पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली द्वारा जवाब दिया गया कि इस जिला से सम्बन्धित नहीं है। उन्होंने कहा कि सूचना दिल्ली के कार्यालयों में इधर से उधर धूमती रही लेकिन किसी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ भी लिखने से परहेज रखा, सरकारी कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का जवाब ना देकर यह साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, जो कि देश के लिए सबसे बड़ी विडम्बना है।

शोध पद्धति पर दस दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18 मार्च से

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। संगम विश्वविद्यालय के प्रबंध संकाय में 18 मार्च से 27 मार्च तक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रायोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में देशभर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के 30 शोधार्थी भाग लेंगे। कार्यशाला के तहत अनुसंधान पद्धति से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें प्रकल्पना निर्माण, अनुसंधान उद्देश्यों की पहचान, साहित्य समीक्षा, नमूना विधियाँ, डेटा संग्रह, सांख्यिकीय उपकरण एवं तकनीक, अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना एवं एआई का उपयोग शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रो. आनंद पालीवाल (पूर्व सदस्य, भारतीय विधि आयोग एवं अधिष्ठाता, विधि विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर) होंगे। साथ ही प्रो. अमरेंद्र पाण्डे (हेड ऑफ रिसर्च डिवीजन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) और डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी (प्राचार्य, एमएलवी कॉलेज, भीलवाड़ा) बतौर मुख्य वक्ता कार्यशाला में अपने विचार साझा करेंगे। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. करुनेश सक्सेना ने इसे विश्वविद्यालय के लिए एक



गरिमामयी उपलब्धि बताया और कहा कि शोध को बढ़ाने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। उप कुलपति प्रो. मानस रंजन पाणिग्रही ने इसे शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी कार्यशाला करार दिया और कहा कि देश में शोध गुणवत्ता बढ़ेगी। कुलसचिव प्रो. राजीव मेहता ने विभाग को इस कार्य हेतु शुभकामनाएं प्रदान की। परिचयना नदेशक डॉ. तनुजा सिंह ने बताया कि कार्यशाला में प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि शोधार्थी

इसे शोध कार्य में प्रयोग कर सकें। प्रबंध संकाय के के अधिष्ठाता डॉ. मुकेश शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला में देशभर के विश्वविद्यालयों से शोधार्थी भाग लेंगे, जिनमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, कोटा विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, दयालबाग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, मंदसौर विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, मनिपाल विश्वविद्यालय जयपुर, बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय एवं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, भोपाल नोबल विश्वविद्यालय उदयपुर आदि शामिल हैं।

जिन्दगी जीने दो अपलक...!



किसरा मंडल बंडलागुडा व चिरीयाला जौन स्थित श्री आईजी सेवा संघ में आदविक मुलेवा दूदोत्सव व डोयटन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सीरवी समाज गणमान्य पदाधिकारी भंगाराम मुलेवा, भंवरलाल मुलेवा सोहनलाल हाम्बड़, मांगीलाल काग, कालुराम काग, डायाराम लवेटा, प्रभुराम परिहारिया, तुलसाराम सिन्दडॉ, अर्जुनलाल बर्वा, किशनसिंह राठौड़, नारायणलाल परिहार, हुक्माराम सानपुरा, कालुराम काग चितल, मोतीलाल काग, ओमप्रकाश पंवार, गौधारीलाल चोयल, मोतीलाल मादावत, भोमाराम चोयल, मलाराम चोयल, सुरेश सेणवा, नेमाराम हाम्बड़, जगदीश काग, मंगल मुलेवा, जगदीश सीरवी, बाबूलाल मुलेवा, पारसमल शर्मा, ओंकारलाल हाम्बड़, बाबूलाल मुलेवा, गोपाराम लिकमाराम सोहनलाल, महेश, महेंद्र, ओमप्रकाश, पुकराज, कानाराम, मोहनलाल, धर्मीचंद मुलेवा परिवार व समाज बन्धु।

सरकार ने खनन लुटेरों के लिए खोला छोड़ दिया; पूरे प्रदेश में माफिया सक्रिय, पुलिस निष्क्रिय

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने राज्य में खनिज लूट का माहौल बना दिया है। इसका नेटवर्क सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक फैला हुआ है। सुबह से शाम तक हर कोई इसके शिकार पर लगा रहता है। कुछ इसी तरह की बात कहते हुए बीजद ने आज खनन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन माझी पर निशाना साधा है। बीजद विधायक ब्यामकेश राय ने भी कहा कि खदान मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां अवैध खनन हो रहा है वहां कोई कार्रवाई नहीं की



जा रही है। खनन माफिया दिनदहाड़े चोरी कर रहे हैं। सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध खनन हो रहा है। इसका पैसा विधायकों के माध्यम से



रघुवर सरकार के पांच मंत्रियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत
कार्तिक कुमार परिय्या, स्टेट हेड झारखंड
रांची, झारखंड में रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ ने खारिज कर दी गयी है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अमर कुमार बाबरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, तुईस मरांडी तथा डॉ. नीरा यादव की आय से श्रधिक संपत्ति मामले में दायित्व पीआईएल सुनवाई के बाद खारिज कर दी. ये सभी तत्कालीन रघुवर दास सरकार में मंत्री थे. वर्ष 2020 में पंकज कुमार यादव बाजक व्यक्तित्व ने आय से श्रधिक संपत्ति को लेकर एक पी आई एन प्रारंभ दायर की थी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन.एच. राय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सोमवार को तत्कालीन रघुवर दास सरकार के मंत्री अमर कुमार बाबरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, तुईस मरांडी और डॉ. नीरा यादव के खिलाफ हाईकोर्ट ने दायित्व पीआईएल पर सुनवाई हुई. इसके बाद खंडपीठ ने आय से श्रधिक संपत्ति से जुड़ी जम्बित याचिका खारिज कर दिया है। खवि तत्कालीन भाजपा मंत्री तुईस मरांडी अब झारखंड उच्च न्यायालय की विचारण करे।

टाटा का गैंगस्टर मनीष ने किया आत्मसमर्पण

के०के० परिच्छा, स्टेट हेड, झारखंड

जमशेदपुर, शहर के जुगसलाई इलाके का गैंगस्टर मनीष सिंह ने आज पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। मनीष का कांग्रेसी नेता अभिजित सिंह पर फायरिंग का आरोप है। वह पुलिस से बच कर चल रहा था। उस पर हत्या फिरोती के क ई मामले दर्ज हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अगस्त महीने में जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित गर्ल्स स्कूल रोड के पास कांग्रेसी नेता अभिजित सिंह के कार्यालय के पास गोली चालन की घटना घटी थी। इस घटना में अभिजित सिंह को निशाना बनाकर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की थी। गोलीबारी में अभिजित सिंह बाल-बाल बच गए थे, लेकिन इस हमले के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अभिजित सिंह के बयान पर पुलिस ने



मनीष सिंह और उसके सहयोगियों को इस मामले में नामजद आरोपी बनाया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गैंगस्टर मनीष सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने पहले ही मनीष सिंह के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मनीष सिंह फरार चल रहा था। पुलिस के द्वारा कई स्थानों पर

छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद जुगसलाई थाना प्रभारी सचिन दास ने पुलिस की टीम को और भी सक्रिय किया और मनीष सिंह को दबाव में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। पुलिस के प्रयासों के बाद मनीष सिंह ने आज खुद ही जुगसलाई थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।

इस श्वहार पर जिसने भी पैर धरा, पहले तो जीवन रजियार फिर मरा। सुख-दुख की संवेदना हुआ खडा, जमाने की अवहेलना से खुब लडा। डिग्रियों का तमगा ले शिखर चडा, तकनीक के अभाव में पीछे ही रहा।